# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

## (सत्र 2016-17 के लिए आवेदन करने हेतु संबद्ध निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) संबद्धता आदेश से अलग है? | एनसीटीई ने पहली बार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन के साथ संबद्धता निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करने की आवश्यकता की शुरुआत की है।<br>विनियम 2014 के लागू होने तक, संबद्ध निकायों के बीच यह भावना थी कि विश्वविद्यालयों/संबद्ध निकायों की भूमिका को कमतर आंका गया है, क्योंकि वे किसी भी स्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे और एक बार एनसीटीई मान्यता प्रदान करता है, तो संबद्ध निकायों के लिए संबद्धता प्रदान करना बाध्यता बन जाती है। एनसीटीई ने महसूस किया कि संबद्ध निकायों के विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस प्रकार एक नया अध्यापक शिक्षा संस्थान स्थापित करने और/या एक नए कार्यक्रम या अतिरिक्त प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में संबद्ध निकायों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का प्रावधान पेश किया गया है। नए विनियमों के अनुसार, एनसीटीई में आवेदन करने से पहले किसी संस्थान को संबंधित संबद्ध निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। यह एनओसी बाद में आवेदनों के प्रसंस्करण के दौरान राज्य सरकार से मांगे गए एनओसी से अलग है।<br>संबद्धता निकायों द्वारा जारी यह एनओसी आवेदन करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी विनियम 2014 के तहत किया गया प्रावधान है। |
| 2. | यह राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) से किस प्रकार भिन्न है? | राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सरकार की नीति पर आधारित होता है, जो मांग और आपूर्ति की स्थिति, प्रस्तावित संस्थान के स्थान पर अध्यापक शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता आदि, जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जब एनसीटीई, एनओसी जारी करने के लिए आवेदन की प्रति के साथ राज्य सरकार को एक पत्र भेजती है, तो वह एक अवधि निर्दिष्ट करती है, जिसके पहले राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें भेजनी होती हैं; और यदि राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देती है, तो एनसीटीई आवेदन की प्रक्रिया पर आगे कार्य करती है। संस्थान द्वारा राज्य सरकार की एनओसी के बिना आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और बाद में एनसीटीई द्वारा संबंधित राज्य सरकार को/उसकी सिफारिशें मांगने के लिए अग्रेषित किया जाता है।<br>आवेदक को आवेदन के साथ संबद्ध विश्वविद्यालय या किसी अन्य संबद्ध निकाय से एनओसी जमा कराना होता है। संबद्ध निकाय को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रस्तावित संस्थान उनके अधिकार क्षेत्र में है और यदि एनसीटीई किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए अनुमति देता है, तो वह छात्रों की परीक्षा संचालित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि उसने किसी संस्थान द्वारा आवेदन किए गए पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और परीक्षा योजना तैयार नहीं की है, तो वह एनओसी देने से मना कर सकता है। यदि किसी संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संबद्ध निकाय का एनओसी नहीं है, तो एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति द्वारा उस पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। तथापि, आवेदक संस्थान द्वारा एनओसी जमा करने से वह स्वतः ही मान्यता के लिए पात्र नहीं हो जाता है। |
| 3. | अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए? | संबद्धता प्रदान करने वाली संस्थाएँ अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड और प्रक्रियाएँ विकसित कर सकती हैं। मुख्य रूप से उन्हें परीक्षा संचालित करने और प्रमाणन के लिए अपनी सहमति देनी होगी। आम तौर पर, कॉलेज विकास परिषद, जो संबद्धता से संबंधित है, सोसायटी/प्रबंधन की साख, उस जिले या इलाके में ऐसे अध्यापक शिक्षा |

| | | |
|---|---|---|
| | | कार्यक्रम/संस्थान की आवश्यकता, विश्वविद्यालय की संबद्धता को संभालने की क्षमता आदि, जैसे कारकों के आधार पर इसे ले सकती है। |
| 4. | क्या राज्य सरकार को पूरे राज्य में सभी संबद्ध निकायों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए एक समान मानदंड जारी करने के लिए कहा जाना चाहिए? | संबद्ध निकाय इसे अपने-अपने राज्य सरकारों के ध्यान में लाएं तथा उन पर एक समान नीति बनाने के लिए समन्वय तंत्र स्थापित करने का दबाव डाल सकती हैं। |
| 5. | क्या शिक्षा विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है? या फिर क्या यह विश्वविद्यालय की कॉलेज विकास परिषद है और एससीईआरटी में ऐसी कोई व्यवस्था है, जो एनओसी जारी करने वाली एजेंसी है? | विश्वविद्यालयों के मामले में, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) इस उद्देश्य के लिए अधिकृत अधिकारी/प्राधिकरण (जैसे निदेशक, कॉलेज विकास परिषद) द्वारा कुलपति के अनुमोदन से जारी किया जाना चाहिए। एससीईआरटी/बोर्ड के मामले में, इस उद्देश्य के लिए एनओसी निदेशक/अध्यक्ष के अनुमोदन से अधिकृत अधिकारी (राज्य शिक्षा विभाग के परामर्श से) द्वारा जारी किया जाएगा। |
| 6. | विश्वविद्यालय को एनसीटीई को आवेदन करने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) क्यों देना चाहिए? इसके बजाय, आवेदन को संबद्ध निकायों के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जा सकता है। | जारी किया जाने वाला एनओसी मुख्य रूप से अधिकार क्षेत्र, कार्यक्रम की उपलब्धता, परीक्षा संचालित करने की तत्परता और इच्छा आदि के संबंध में होता है। संबद्धता प्रदान करने वाली संस्था, यदि चाहे तो, राज्य सरकार से अनुमोदन ले सकती है। राज्य सरकार द्वारा एनओसी का उद्देश्य विभिन्न विचारों पर आधारित होता है, जिस पर राज्य सरकार आवेदन संसाधित होने के बाद निर्णय लेगी। |
| 7. | मान्यता, सम्बद्धता और प्रवेश कैलेंडर एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। इसमें ओवरलैप् हैं। विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष के उत्तरार्ध में सम्बद्धता प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद एनसीटीई अगले वर्ष के लिए मान्यता जारी कर रही है। | नियमानुसार मान्यता और संबद्धता कैलेंडर में कोई ओवरलैप नहीं है। माँ वैष्णोदेवी मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता, संबद्धता और प्रवेश के लिए पहले से ही तिथि सीमा निर्धारित कर दी है, जो सभी संबंधितों अर्थात एनसीटीई, विश्वविद्यालयों और अन्य संबद्ध निकायों और संस्थानों के लिए बाध्यकारी है। तिथि की समय-सीमा का पालन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कोई भी विचलन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना हो सकती है। |
| 8. | क्या विश्वविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए अपने संबद्धता मानदंडों में बदलाव करना चाहिए क्योंकि, वे पुराने मानदंडों का पालन कर रहे हैं? | संबद्ध निकाय, एनसीटीई विनियम, 2014 और मां वैष्णो देवी मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए अपने संबद्धता मानदंडों को संशोधित कर सकते हैं। |
| 9. | मौजूदा बीएड कॉलेजों में पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं और इससे मौजूदा समस्याएं और बढ़ गई हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है। अभी तक इसके लिए कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ है। | संबद्धता प्रदान करने वाले निकायों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए अपने स्वयं के तंत्र और प्रक्रियाएं विकसित करनी होंगी। |
| 10. | क्या विश्वविद्यालय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए शुल्क प्रभारित कर सकते हैं? | संबद्धता प्रदान करने वाले निकाय अपने-अपने राज्य सरकारों के परामर्श से इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। एनसीटीई ने इस प्रयोजन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया है। |
| 11. | अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद, यदि कोई संस्था बाद में संबद्धता मानदंडों से विचलित होती है, तो संबद्धता प्रदान करने वाली संस्था क्या कर सकती है? | ऐसे मामलों को संबद्धता प्रदान करने वाले निकाय अपने नियमों के तहत निपटा सकते हैं या मामले को एनसीटीई को भेज सकते हैं। |